Wheat crisis threatening food security

2057. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the article captioned "Wheat crisis threatens food security" by Shri Devindra Sharma, published in the Hindustan Times of 24th April, 1997, has been studied by Government;

(b) if so, what is its perception about the issues raised therein;

(c) whether any steps are being initiated to overcome the crisis; and

(d) if yes, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANS PRASAD SINGH): (a) to (d) The newspaper article suggested that price alone was not enough to boost production of wheat and drew attention to the drastic slump in the growth rate of wheat, need to improve yield, erosion of natural resources affecting the production, excess use of chemical/fertilizers and its impact.

The fall in production of wheat during 1995-96, as compared to 1994-95, and the import of wheat should not be construed to have threatened Food Security of the country. In fact, during 1996-97, the wheat production has been estimated at 68.71 million tonnes as against the target of 65 million tonnes. To increase the production and productivity of wheat, various Crop production programmes, namely ICDP-Wheat, ICDP-Rice and ICDP-coarse cereals, are being implemented in the country.

रिफाइंड तेल में कोलस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का नहीं होना

2058. **श्री राघवजी :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में बेचे जा रहे किसी भी रिफाइंड तेल में कोलस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिफाइंड तेलों के डिब्बों पर यह लिखा जाए कि "यह तेल कोल स्ट्रॉल मुक्त नहीं है" ताकि आम जनता गुमराह न हो ?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। रसायनों की मदद से तेलों को शुद्ध करने की परम्परागत प्रक्रिया से रंग के साथ-साथ "स्ट्रोल्स" का एक भाग खत्म हो जाता है। रिफाइंड तेलों में "कोलस्ट्रॉल" तत्व शून्य से नगण्य होते हैं।

माप एवं तौल विभाग द्वारा टेलीफोन और बिजली के मीटरों का सत्यापन

2059. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माप एवं तौल विभाग द्वारा टेलीफोन और बिजली के मीटरों का सत्यापन किया जाता है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भंडारण हेतु समुचित व्यवस्था है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या नए गोदाम बनाने की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्षमता और स्थान संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) खाद्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के लिए धान से 67/68 प्रतिशत चावल रिकवरी निश्चित किए जाने का क्या आधार है ; और

(च) सर्वश्री मसूरी धान के लिए उत्तम श्रेणी में किन-किन राज्यों में समर्थन मूल्य दिया जा रहा है ; क्या मध्य प्रदेश में भी इसे उत्तम श्रेणी के अन्तर्गत उपार्जित किया जाएगा ?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

भारतीय खाद्य निगम के पास मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण क्षमता है। 31.05.1997 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 7.35 लाख मी. टन की भंडारण क्षमता थी और क्षमता उपयोग 61 प्रतिशत था जिनका ब्यौरा निम्नवत है :—

भारतीय खाद्य निगम	राजस्व	क्षमता	उपयोग
जिले	जिले	(लाख मी. टन में)	
रायपुर	रायपुर	3.77	66%
बिलासपुर	बिलासपुर रायगढ़ शहडोल सरगुजा	1.87	58%
दुर्ग	दुर्ग बस्तर राजनन्दगांव	1.71	53%
कुल :		7.35	61%

(ग) और (घ) इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1997–98 के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धमावी में 10,000 मी. टन क्षमता के एक नये गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ङ) विभिन्न राज्य सरकारों और चावल मिल मालिकों के एसोसिएशनों की लगातार इस मांग पर कि वैज्ञानिक आधार पर एक अधिक तथ्यपरक आउट टर्न अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए, खाद्य मंत्रालय ने सितम्बर, 1993 में भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिया था कि वे संबंधित राज्य सरकारों और चावल मिल मालिकों के एसोसिएशनों के सहयोग से धान के ट्रायल मिलिंग के एक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दें। तदनुसार ट्रायल मिलिंग के प्रयोगों के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए अक्तूबर, 1993 और जनवरी, 1994 के बीच एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। सी. एफ. टी. आर. आई. मैसूर, आई. आई. टी., खड़गपुर और पी. जी. आर. ओ., तंजाऊर संस्थानों को प्रस्तावित अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। इन संस्थानों की रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर धान से चावल बनाने का आउट टर्न अनुपात मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सभी किस्म के धान के लिए धान को बिना उबाले चावल बनाने के संबंध में 67 प्रतिशत और धान को उबालकर चावल बनाने के संबंध में 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

(च) धान/चावल की किस्में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत की जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार लम्बाई/चौड़ाई अनुपात के आधार पर धान/चावल को अधिप्राप्ति करता है।

सवर्ण मसूरी या स्वर्ण मसूरी नामक धान की किस्म भारत सरकार द्वारा अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत की गई है। इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	किस्म का नाम	समूह का वर्गीकरण
उड़ीसा	सवर्ण मसूरी मसूरी	फाईन
कर्नाटक	सोना मसूरी	फाईन
आंध्र प्रदेश	सवर्ण	फाईन
मध्य प्रदेश	मसूरी	फाईन
गुजरात	मसूरी	कॉमन
त्रिपुरा	मसूरी	सुपर फाईन
उत्तर प्रदेश	मसूरी	सुपर फाईन

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा राजसहायता दिया जाना

2060. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजसहायता दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एककों/क्षेत्रों को राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राजसहायता के भुगतान हेतु जिला-वार, उद्योग-वार दावे लंबित हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या ऐसे दावों के भुगतान के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च) मंत्रालय की योजना स्कीमें क्षेत्र विशेष नहीं होतीं। योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वयंसेवी संगठनों आदि से प्राप्त